



DELHI POLICE 2025

CONSTABLE HCM AWO/TPO DRIVER



यकीन बैच

POLITY

भारत के संवैधानिक विकास

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF INDIA **Part -4**



LIVE
STREAMING

10-04-2025 12:05 PM

Polity → भारत का संवैधानिक विकास / (Constitutional development)

1853 का राजपत्र / Charter act - 1853 :- "अन्तिम-चार्टर एक्ट"

भारतीयों द्वारा कम्पनी के शासन को खत्म की मांग की।

① गवर्नर-जनरल डलहौजी ने कम्पनी के शासन में सुधार के लिए :- अधिनियम / Act बनाया।
↳ विधायी कार्य [Legislative work] एवं प्रशासनिक कार्य [Administrative work] को अलग-अलग / Separate कर दिया

② विधायी कार्य / Legislative work या कानून बनाने के लिये [Law making] विधान परिषद जिसे All India Legislative Council कहा गया - इसमें कुल सदस्य / Total Members - 12 थे

↓
पूरे भारत के लिये कानून / Law बना सकती हैं

③ → बंगाल के प्रशासन के लिये [for the Administration of Bengal] - एक लैफ्टिनेंट गवर्नर [Lt. Governor] की नियुक्ति की गयी।

④ विधि सदस्य [Law Member] को गवर्नर-जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बनाया।

⑤ कम्पनी में कर्मचारियों की नियुक्ति [Appointment of employees in company] प्रतियोगी परीक्षा [Competitive Exam] के आधार पर होगा।

⑥ निर्देशक मण्डल [Board of directors] → 24 से कम करके 18 कर दी
6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत / Nominated by British Crown.

भारत का संवैधानिक विकास / Constitutional development of India

ब्रिटिश क्राउन [1858-1947] के अन्तर्गत [Under the British crown]

⇒ भारत शासन अधि० - 1858 / GoI - 1858

ब्रिटिश प्रधानमंत्री - पामस्टन ने भारत में शासन की कमियों [Defects of Rule] को खत्म करने के लिये 12 Feb - 1858 में विधेयक / Bill ब्रिटिश संसद / British Parliament में पेश किया → पास नहीं हुआ, → PM - पामस्टन ने त्याग पत्र दिया।

⇒ नया PM → डरबी / Derby बना → 2 Aug - 1858 में रानी विक्टोरिया से पास कराया।

① इस अधिनियम / Act → भारत का गवर्नर जनरल भारत का "वायसरॉय / Viceroy" बना केनिंग ने पठा।
↳ last - "केनिंग"
↳ प्रथम → केनिंग

इस अधिनियम द्वारा: - Board of Directors (निदेशक मण्डल) एवं Board of Control (नियन्त्रक मण्डल) को समाप्त किया।

के समस्त अधिकार → नया पद / New post → [भारत सचिव] को दिये।

③ ⇒ भारत सचिव [Secretary of State for India] की सहायता के लिये - 15 सदस्यों की एक एक भारत परिषद [India Council] बनायी गयी।

8 सदस्य → ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त

④ - भारत सचिव एवं सदस्यों को वेतन / salary - भारतीय राजस्व Indian Revenue से दी जायेगी।

7 सदस्य → कम्पनी के Directors द्वारा

⑤ गवर्नर-जनरल की परिषद में Law Member / विधि सदस्य एवं Advocate General की नियुक्ति - ब्रिटिश क्राउन (सम्राट) द्वारा।

Imp ⑥ भारत बजट पेश किया
↳ पहला बजट - 1861 में "जेम्स विल्सन" द्वारा पेश
↳ बजट का जनक / Father of Budget

⑦ भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम - 1861 [Indian Court Act - 1861]